

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2019

देवकरण व अन्य निवासी ग्राम देवगॉव तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:- श्री अनुराग पाण्डे वकील- प्रार्थी

तहसीलदार केकड़ी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 3.12.19

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम देवगॉव पटवार हल्का देवगॉव तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 20141 के खाता संख्या 633 के खसरा नंबर 751/3 मिन रकबा 3.10.00 बीघा किस्म बाराणी 3 लादू पुत्र घीसा कौम बागरिया सा0देह गैर खातेदार दर्ज होकर नामा0 संख्या 402 दिनांक 27.05.1992 से खातेदार दर्ज हुआ है। उक्त आराजी नां0 संख्या 192 दिनांक 26.06.1984 से लादू पुत्र घीसा बागरिया गैर खातेदार को आवंटित हुई है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नंबर 751/3 के बने नये नंबर 3606 रकबा 0.85 है0 में से 3.10.00 बीघा यानि 0.56 एयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में तहसीलदार केकड़ी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./19/9957 दिनांक 26.02.19 का अवलोकन किया गया, तथा पटवारी रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने स्वयं के पिता के नाम भूमि आवंटन का कोई दस्तावेजात सबूत यथा आवंटन आदेश, पट्टा विलेख व आवंटन सूची रजिस्टर की प्रमाणित नकले प्रस्तुत नहीं की हैं। तथा संवत् 2058 की आधार जमाबंदी में सिवायचक अंकित होने के बावजूद दिनांक 30.05.19 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र में 12 वर्ष से अधिक विलंब होने का कोई ठोस कारण भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। आवंटनी लादू का कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजात गिरदावरी पी014 की नकले प्रस्तुत नहीं की हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने के अलावा कोई विकल्प न्यायालय के पास उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन पाया जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी यदि आवश्यक समझे तो नियमानुसार दावा संबंधित न्यायालय में पेश कर अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

